Institute for Ecology and Livelihood Action

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य के आदवासी मछुआरा समुदायों ने अपने पहली बार अपने जलाशय के बचाव, मत्स्य सम्पदा के संरक्षण और मछुआरों के अधिकार की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाई

विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर जयसमंद के मछुआरा समुदाय द्वारा कार्यक्रम आयोजित

उदयपुर, 4 फरवरी 2023. विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर पारिस्थिकी एवं आजीविका कार्य संस्थान (इंस्टिट्यूट फॉर इकोलॉजी एंड लाइवलीहुड एक्शन) उदयपुर तथा छोटे मछुआरों का राष्ट्रीय संगठन (नेशनल प्लेटफार्म फॉर स्माल स्केल फिश वर्कर्स) के साथ जयसमंद झील के मछुआरा समुदायों द्वारा संयुक्त रूप से जयसमंद झील के किनारे संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयसमंद झील से लगे गाँवों की मत्स्य उत्पादक सहकारी समितियों के अध्यक्ष, व्यवस्थापकों एवं मछुआरा परिवारों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

पारिस्थिकी एवं आजीविका कार्य संस्थान के प्रबंध न्यासी वीरेन लोबो ने बताया कि पूरी दुनिया में स्थानीय जलाशयों पर मानव जनित भयानक संकट है और छोटे मछुआरों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जयसमंद झील से लगे 22 गांवों में मत्स्य उत्पादक सहकारी समितियां गठित हैं, और इनमें लगभग 2500 मछुआरा परिवार जुड़े हुए हैं जिनकी कुल आबादी 12000 से अधिक है। इन मत्स्य उत्पादक सहकारी समितियों को पहले राजस संघ के द्वारा प्रबंधित किया जाता था और इन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाता था। किन्तु बाद में इन्हें मत्स्य निदेशालय के अधीन कर दिया गया जिसके बाद इन मछुआरों की स्थिति विभागीय अनदेखी और खानापूर्ति कामों से बिगड़ती गयी। झील में निदेशालय द्वारा मनमर्जी से अन्य दूरस्थ राज्यों से चयनित प्रजातियों के बीज मंगाकर डाले गए जिसके कारण झील की मत्स्य विविधता नष्ट होती गयी। भू-माफिया और रसूखदारों द्वारा जयसमंद झील अंदर टापुओं पर और चारों ओर अतिक्रमण किये जा रहे हैं, झील के प्राकृतिक स्वरुप और पारिस्थितिकी तंत्र को जमकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सरकारी तंत्र के मकड़जालों में उलझे इन आदिवासी मछुआरों को न तो क्लोज सीजन (जब मानसून काल के दौरान

मत्स्याखेट बंद रहता है) के दौरान 'सेविंग कम रिलीफ' योजना के द्वारा पर्याप्त गुजरा भत्ता दिया जाता है, और उसमें भी इन गरीब मछुआरों को गरीबी की रेखा के नीचे और ऊपर की श्रेणियों में बाँट कर अधिकाँश परिवारों को गुजरा भत्ता से वंचित किया जा रहा है।

पारिस्थितिकी वैज्ञानिक एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की आनुशंगिक इकाई आईयूसीएन के विश्व आयोग सदस्य डा. सुनील दुबे ने बताया कि जयसमंद झील में विदेशी घुसपैठी प्रजाति 'तिलापिआ मछली' को डाल कर सरकारी विभाग ने न केवल जयसमंद झील की स्थानीय मत्स्य प्रजातियों के विनाश का बीज बो दिया बल्कि उसके साथ स्थानीय आदिवासी मछुआरा समुदायों की आजीविका और जीवनयापन के ऊपर भी दिनोंदिन बढ़ते संकट की नींव डाल दी। आज न केवल भारत बल्कि विश्व की बड़ी और महत्वपूर्ण कृत्रिम झीलों में से एक जयसमंद झील के अस्तित्व पर मानवीय क्रियाकलापों से भयंकर संकट व्याप्त हो चुका है। स्थानीय आदिवासी मछुआरे इस झील के असली संरक्षक हैं और महाराणा जयसिंह ने भी अपने आदिवासी जनता के लिए इस झील का निर्माण करवाया था, किन्तु आज मत्स्य निदेशालय के लचर तंत्र के कारण झील की मत्स्य विविधता और मछुआरों की आजीविका भयंकर संकट में हैं।

स्थानीय मछुआरे और मत्स्य उत्पादक सहकारी समिति मिण्डुदा के व्यवस्थापक श्री गोविन्द मीणा ने जयसमंद झील के पारिस्थितिक कार्यों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को उनके प्राचीन प्राकृतिक रूप में संरक्षित करने की आवश्यकता बताई और सर्कल से मांग की कि झील के मछली आवास एवं प्रजनन क्षेत्रों में विनाशकारी पर्यटन, प्रदूषण, निर्माण, वाणिज्यिक गतिविधियों को रोका जाए।

कार्यक्रम में मत्स्य उत्पादक सहकारी समिति के मैथुडी के व्यवस्थापक केशुलाल तथा अध्यक्ष मेगाराम, पानीकोटड़ा समिति के व्यवस्थापक शंकरलाल, पाटन समिति के व्यवस्थापक रतनलाल, चिबोड़ा समिति के दौलतराम, तोरणमहुड़ी समिति के व्यवस्थापक रामलाल इत्यादि ने भी सम्बोधित किया और सरकार से मांग की कि उन्हें पुनः राजस संघ के अंतर्गत लिया जाये और मत्स्य निदेशालय द्वारा किये गए मनमाने निर्णय और अनदेखी से बचाया जाये। समिति सदस्यों में से नाथूलाल, शंकरलाल, मोताराम, रूपलाल, धुलीराम, होमाराम, देवीलाल ने भी आपने विचार रखते हुए सरकार से मांग की कि अन्य राज्यों से मत्स्य बीज न मंगवाकर उन्हें ही स्थानीय स्तर पर मत्स्य बीज उत्पादन करने और आपसी सहमति से झील में मत्स्य बीज डालने की व्यवस्था की जाये, मछली की खुली बिक्री के लिए उदयपुर शहर और आसपास के कस्बों में मंडियों स्थान प्रदान किया जाये, मछली प्रसंस्करण के प्रशिक्षण और मछली उत्पाद बिक्री के लिए मछुआरा महिलाओं एवं युवाओं की क्षमतासंवर्धन और आर्थिक सहयोग दिया जाये,

मछुआरों को भी मत्स्य उतपादन के लिए बैंक द्वारा लोन दिया जाये और अनावश्यक गारंटी मांगना बंद किया जाये। जिस प्रकार वनों पर निर्भर रहनेवाले वनवासियों को सरकार अधिकार प्रदान कर रही है उसी प्रकार मत्स्य संसाधनों आजीविका और जीवनयापन के लिए निर्भर रहने वाले आदिवासी मछुआरों को भी उनके जलाशय और मत्स्य संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन के अधिकार दिए जाएँ और सरकारी तंत्र को दुरुस्त कर सहयोग प्रदान किया जाये।

कार्यक्रम में मैथुडी, पाटन, चिबोड़ा, पानीकोटड़ा, हीरावत, तोरणमहुड़ी, घाटी, सियारकोटड़ा, बोडला, माकड़सीमा, देवड़ातालाब, पायरी के मछुआरा प्रतिनिधियों व मछुआरा परवार सदस्यों ने भाग लिया।

यह कार्यक्रम विश्व आर्द्रभूमि दिवस की अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट पर भी रजिस्टर किया गया है और इसके माध्यम से जयसमंद के मछुआरों की बात राज्य सरकार, भारत सरकार के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इत्यादि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तक पहुंचाई जाएगी।

सादर प्रकाशनार्थ

वीरेन लोबो
प्रबंध न्यासी
पारिस्थिकी एवं आजीविका कार्य संस्थान
9460573746
डा. सुनील दुबे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक 7014920553